Registered with the Registrar of News Paper (Govt. of India) Vide R.N.I. No. 39299/81

On The Way Half Century 50

मूल्य एक प्रति 3.00 रु.

Monday & Tuesday every week on Delhi Postal Regd. No. DL(E)-20/5174/2021-23

व्यापार एक्सप्रेस

(हिन्दी साप्ताहिक)

Office : 2718, Street No. 5, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-110032
Mob.: +91-9312625326, 9717513928
Email: vyaparexpress50@gmail.com, vyaparexpress@ymail.com

CHIEF EDITOR : T.R. ARORA
www.vyaparexpress.co

वर्ष 42 अंक 08 • 21 फरवरी 2022 – 27 फरवरी 2022 प्रकाशन की तिथि हर सोमवार वार्षिक मूल्य सप्लीमेंट्री सहित 1100/– पृष्ठ–4

मिर्च और कपास की कीमतों में बढ़ोत्तरी से फायदा ले रहे किसान

सूखी मिर्च और कपास की कीमतों में काफी तेजी देखी जा रही है। बढ़े हुए दाम का लाभ किसानों को मिल रहा है। इस बार कीटों के हमले से कपास और सूखी मिर्च की फसल काफी प्रभावित हुई थी, जिससे उत्पादन कम हुआ है। सीमित मात्रा में बाजार में आवक के कारण इन दोनों फसलों की कीमत बढ़ गई है। हालांकि इसका लाभ किसानों को मिल रहा है, जिनकी पैदावार प्रभावित हुई है। कम उत्पादन के कारण ही व्यापारी ऊंची दरों पर खरीद कर इसे स्टॉक कर रहे हैं। व्यापारियों को स्थानीय और विदेशी बाजारों में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसी वजह से मंडी में आ रही पैदावार को किसी भी भाव पर खरीद ले रहे हैं, उन्हें आगे इससे मुनाफा कमाने की संभावना है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, सूखी मिर्च की चर्चित किस्मों की कीमत 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल थी। लेकिन इस बार रेट 20 हजार के ऊपर जा पहुंचा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सूखी मिर्च की सबसे अधिक खेती होती है। उत्पादन के मामले में भी ये दोनों राज्य काफी आगे हैं। अनुमान के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले का पूरे राज्य के उत्पादन का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा रहता है। लेकिन इस बार थ्रिप्स कीट के हमले के कारण उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, बढ़ी हुई कीमतों से किसान पैदावार में आई गिरावट की भरपाई कर सकेंगे या नहीं, यह तो कुछ दिन बात पता चलेगा। लेकिन दाम बढ़ने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है। अब घरेलू मांग भी बढ़ रही है और उत्पादन में कमी आई है। इस वजह से दाम में तेजी देखने को मिल रही है। थ्रिप्स कीट के हमले के बाद किसी भी राज्य ने सूखी मिर्च के अनुमानित उत्पादन का आंकड़ा नहीं दिया है। ऐसे में व्यापारी अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं कि कितनी पैदावार बाजार में आएगी। ऊंचे दाम पर खरीद का यह भी एक कारण है। वहीं कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों के हटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में आने वाली दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं, जिससे अन्य राज्यों में आपूर्ति सुगम हो गई है। मिर्च का निर्यात करने वालों का कहना है कि इस बार जिस तरह से भाव बढ़े हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अगर फसल पर कीट का हमला नहीं हुआ होता तो किसानों को काफी फायदा होता।

चावल निर्यात में भारत के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खडी कर सकता है थाईलैंड

थाईलैंड इस साल वैश्विक चावल बाजार में भारत के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा खडी कर सकता है। चावल के व्यापार के पारबोल्ड सेगमेंट में यह भारत का एकमात्र प्रतियोगी है। वर्ष 2019 और 2020 में कम उत्पादन की वजह से थाईलैंड इस प्रतिस्पर्धा से बाहर था। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के मुताबिक, वर्ष 2021–22 सीजन के दौरान थाईलैंड का चावल उत्पादन 208 लाख टन होने का अनुमान है। यह उत्पादन वर्ष 2020–21 में 188 लाख टन और 2019–20 में 176.5 लाख टन था। पानी की बेहतर उपलब्धता से उत्पादन में सुधार की उम्मीद है, जबकि 2019 और 2020 के दौरान यह अहम मुद्दा था।

उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, थाईलैंड का चावल निर्यात इस साल 31 प्रतिशत बढ़कर 80 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल 61 लाख टन था। मुख्य रूप से कमजोर थाई भात (थाईलैंड की करेंसी) को देखते हुए अधिक निर्यात का अनुमान लगाया गया है। ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष का कहना है कि थाईलैंड में उबले हुए चावल की कीमतें भारतीय कीमतों से मेल खाने के लिए घट गई हैं। वे भारतीय कीमतों से 20–30 डॉलर अधिक हैं। वर्तमान में भारतीय पारबोल्ड चावल 5 प्रतिशत टूटा हुआ 370–376 डॉलर प्रति टन बोला जा रहा है जबकि थाईलैंड 395 डॉलर प्रति टन पर ऑफर कर रहा है।

थाईलैंड का निर्यात पिछले साल के 60–65 लाख टन से बढ़कर 80 लाख टन होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, कुछ खरीदारों को थाई चावल खरीदना बेहतर लगता है क्योंकि इसकी गुणवत्ता भारतीय किस्म से बेहतर होती है। इसलिए निर्यात की मात्रा बढ़ने की संभावना है। उबले हुए चावल के लिए ऊंची घरेलू कीमत और परिवहन की समस्याओं ने भारतीय पारबोल्ड चावल के निर्यात पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। यूएसडीए के बैंकॉक एफएएस पोस्ट में कहा गया है कि थाई पारबोल्ड चावल भारतीय पारबोल्ड चावल के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी था और पिछले साल लगभग 44 प्रतिशत निर्यात मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, बेनिन, कैमरून और अंगोला गया। इसमें से 70 फीसदी उबले हुए चावल थे। छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बंदरगाहों तक उबले चावल की आवाजाही रेल रेक की कमी के कारण प्रभावित हुई थी, हालांकि स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में लगभग 20 रुपए प्रति किलो पर उबला हुआ चावल खरीद रही है और इसे व्यापारियों को 24 रुपए में दे रही है, जिससे निर्यातकों के लिए चीजें मुश्किल हो रही हैं। यूएसडीए बैंकॉक एफएएस पोस्ट के मुताबिक थाईलैंड के सफेद और उबले हुए चावल की मजबूत मांग होगी क्योंकि व्यापारियों का अनुमान है कि थाई चावल निर्यात की कीमतें वियतनामी और भारतीय चावल की तुलना में अधिक आकर्षक बनी रहेंगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च में समाप्त होने के बाद से भारतीय निर्यात को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ शिपर्स को स्रोत तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है।

हालांकि, द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि, भारत वैश्विक चावल बाजार में थाईलैंड को टक्कर देने में सक्षम होगा। थाईलैंड के लिए समस्या यह है कि उसके पास चावल की शिपिंग करने वाले कुछ ही निर्यातक हैं, जबकि भारत में कई हैं। इसके अलावा, भारत में कई बंदरगाहों से चावल का निर्यात किया जाता है। सूत्रों के अनुसार, भारत अफ्रीकी गंतव्यों के निकट होने के कारण लॉजिस्टिक लाभ की स्थिति में है। लेकिन देश में निर्यातकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

भारतीय निर्यातक एक–दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हैं। फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों को छोड़कर भारतीय चावल अब लगभग सभी देशों में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने फिलीपींस के राजदूत के साथ एक खरीदार–विक्रेता बैठक आयोजित करने में मदद की, जो हमारे अनुरोध को देखने के लिए सहमत हो गया है। फिलीपींस को निर्यात करने में समस्या यह है कि फिलिपिनो नरम चावल पसंद करते हैं जो वियतनाम आपूर्ति करता है, जबकि भारतीय किस्म कड़क है।

गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान

सॉल्वैंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के मुताबिक, देश का सोयामील (डीओसी) निर्यात जनवरी में सालाना आधार पर 65 प्रतिशत घटकर 1.76 लाख टन रहा। मुख्य रूप से सोयाबीन और रैपसीड मील के निर्यात में गिरावट से डीओसी की बाहर भेजी जाने वाली खेप में कमी आई है। जनवरी, 2021 में भारत का सोयामील निर्यात 5.01 लाख टन रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह अप्रैल–जनवरी के दौरान सोयामील निर्यात 35 प्रतिशत घटकर 19.43 लाख टन रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 29.69 लाख टन रहा था।

सोयामील का इस्तेमाल पॉल्ट्री और अन्य क्षेत्रों में पशुचारे के रूप में होता है। एसईए द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी में सोयाबीन एक्सट्रैक्शन का निर्यात भारी गिरावट के साथ 52,771 टन रह गया, जो एक साल पहले समान महीने में 2.83 लाख टन रहा था। इसी तरह जनवरी में रैपसीड एक्सट्रैक्शन का निर्यात घटकर 16,164 टन पर आ गया, जो एक साल पहले समान महीने में 74,240 टन था।

भारत से चीनी का निर्यात हुआ तीन गुना, उत्पादन में भी बढ़ोतरी

भारतीय चीनी मिल संघ के मुताबिक, देश का चीनी उत्पादन 2021–22 के मार्केटिंग ईयर में 15 फरवरी तक 6 प्रतिशत बढ़कर 220. 91 लाख टन पर पहुंच गया है। इससे पिछले साल की समान अवधि में चीनी उत्पादन 209.11 लाख टन रहा था। चीनी मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर तक होता है। इस्मा ने कहा कि, चीनी निर्यात जनवरी तक तीन गुना होकर 31.5 लाख टन पर पहुंच गया है। संगठन का कहना है कि, इस अवधि में महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन बढ़कर 86.15 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 75.46 लाख टन था। वहीं उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 65.13 लाख टन से घटकर 59.32 लाख टन रह गया। कर्नाटक में उत्पादन बढ़कर 44.85 लाख टन हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 39.07 लाख टन था।

इस्मा ने बताया कि अभी तक करीब 50 लाख टन चीनी निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसमें से 31.50 लाख टन चीनी का 31 जनवरी तक निर्यात हो चुका है। एक साल पहले समान अवधि में चीनी निर्यात 9.20 लाख टन रहा था। करीब आठ लाख टन चीनी का निर्यात इस महीने होना है। वहीं पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड चीनी निर्यात किया था। पिछले साल 30 सितंबर को समाप्त मार्केटिंग ईयर 2020–21 में अनुमानित रूप से रिकॉर्ड 72.3 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा निर्यात इंडोनेशिया को किया गया था।

इंडोनेशिया को अधिकतम निर्यात 18.2 लाख टन, उसके बाद अफगानिस्तान (6,69,525 टन), यूएई (5,24,064 टन) और सोमालिया (4,11,944 टन) को निर्यात किया गया था।

भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है। इस बार भारत के पास निर्यात के लिए बेहतर अवसर है। इसका लाभ चीनी मिलों को मिलेगा। चीनी निर्यात से आए पैसे को चीनी मिलें

किसानों के बकाया भुगतान में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्मा ने कहा कि एथनॉल की बात की जाए, तो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने चौथे चक्र में 95 करोड़ लीटर की मांग दी थी। इसमें से आपूर्तिकर्ता 39 करोड़ लीटर एथनॉल की पेशकश कर चुके हैं।

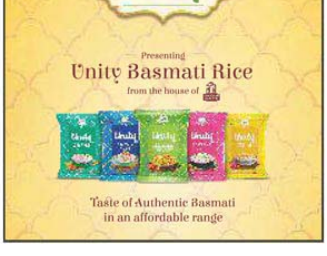

क्षेत्रीय मंडियों के बाजार भाव

कानपुरः गेहूं लूज 2150/2155, जौ 1975/2000, चावल मसूरी 2450/2550, चावल मोटा 2250/2400, देशी चना 5300/5325, चना छना 5850/5950, दाल चना 5900/6000, पिचकी 4800/5000, मटर दाल 7200/7400, अरहर लेमन 6600/6625, दाल अरहर 8900/9300, स्पेशल 8100/8400, उड़द एसक्यू 7250/7260, एफएक्यू 6600/6650, राजमा चित्रा 9900/13100, मूंग 5700/6500, मसूर छोटी 7600/7750, छोटी 8800/9300, सरसों 7300/7350, तिल सफेद 10000/10100 सोया (टीन) 2200/2250, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2550/2600, सरसो खल 3300/3350, पामोलिन 2150/2200, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1850/1950, मधुसूदन देशी घी 6200 वासुदेव 5950, परम प्रीमियम 6250 अलसी 9500/9700, धनिया: लोकल 9700/9800, राजस्थान 102000/10400

लखनऊः गेहूं दड़ा 2130/2140, गेहूं शरबती 2850/2950, चावल शरबती सेला 4000/4050, स्टीम 5050/5150, लालमती 4400/3500, चावल (सोना) 4200/4300, दाल अरहर सवा नं. 7800/7900, पटका 8700/9300 रिजैक्शन 6700/7000, चना दाल 5950/6100, चना देशी छना 5950/6100, चना चापा छना 5900/6000, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत (काला) 7200/8000, दाल उड़द (काली) 7900/8900, उड़द धोया 8000/8800, मसूर छोटी 7500/7700, मलका 8500/8800, किरानाः जीरा 18400/19800 लालमिर्च गुंटूर 17500/2300, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 5600/5700, धनिया एमपी 10100/12200, छोटी इलायची (किलो) 1000/1500, बड़ी इलायची 710/740, कालीमिर्च (किलो) 520/580, सुपारी (किलो) 580/630, सौंफ मोटी 9400/11800, मंगरैल 22500/23500, चिरौंजी (किलो) 1125/1250, मखाना 475/700

मुजफ्फरनगरः चाकू (कोल्ड) 1140/1270, खतौली 3540, देवबंद 3400, थाना भवन 3410, बुढ़ाना 3420, शामली 3390, चीनी हाजिर 3750/3850

हापुड़ः अनाज–दाल गेहूं 2215/2220, चावल परमल 2400/2450, डुप्लीकेट बासमती सेला 6100/6200, बासमती 1121 स्टीम 7400/7500, चना 5200/5250, चनादाल 5800/5900, काबली चना 7000/8500, राजमा देशी चित्रा 11500/13000, दाल अरहर 8000/8800, मसूर 7800/8000, उड़द देसी 6500/6700, दाल उड़द 7500/8500, मूंग यूपी 6500/6800, मूंग दाल 8000/9000, गुड़–चीनीः चीनी हाजिर 3800/3900

कॉटन के वैश्विक उत्पादन के अनुमान में आई कमी

अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने मार्केटिंग वर्ष 2021–22 की फरवरी महीने की रिपोर्ट में भारत और तंजानिया में उपज कम होने से पिछले महीने की तुलना में कॉटन का वैश्विक उत्पादन अनुमान घटाया है। रिपोर्ट में कॉटन की खपत अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है लेकिन अंतिम स्टॉक में कमी की गई है। कॉटन के वैश्विक कारोबार में मामूली कमी आने का अंदेशा जताया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए कॉटन का औसत भाव 90 सेंट्स प्रति पाउंड पर कायम रखा है।

यूएसडीए ने मार्केटिंग वर्ष 2021–22 (अगस्त–जुलाई) की फरवरी 2022 महीने की रिपोर्ट में कॉटन का वैश्विक उत्पादन 2.61 करोड़ टन रहने का अनुमान आंका है जो पिछले महीने 2. 63 करोड़ टन था। यह वर्ष 2020–21 में 2.43 करोड़ टन और वर्ष 2019–20 में 2. 63 करोड़ टन रहा। गांठ में बात की जाए यह उत्पादन अनुमान वर्ष 2021–22 के लिए 12.01 करोड़ गांठ आंका है जबकि वर्ष 2020–21 के लिए 11.17 करोड़ गांठ और वर्ष 2019–20 के लिए 12.10 करोड़ गांठ था। वर्ष 2021–22 में भारत का कॉटन उत्पादन अनुमान पिछले महीने के 59.87 लाख टन से घटाकर 58.79 लाख टन आंका है।

वर्ष 2020–21 में यह उत्पादन 60.09 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 62.05 लाख टन था। यूएसडीए ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में कॉटन की घरेलू खपत वर्ष 2021–22 में 56.61 लाख टन कायम रखी है। यह वर्ष 2020–21 में 54.43 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 43.55 लाख टन थी। भारत का वर्ष 2021–22 कॉटन फसल वर्ष में अंतिम स्टॉक पिछले महीने के 22.08 लाख टन से घटकर 21.42 लाख टन आंका गया है। यह स्टॉक वर्ष 2020–21 में 29.26 लाख टन रहा, जबकि यह वर्ष 2019–20 में 35.24 लाख टन था।

भारत से वर्ष 2021–22 में कॉटन का निर्यात 12.41 लाख टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2020–21 में 13. 48 लाख टन एवं वर्ष 2019–20 में 6.97 लाख टन था। पाकिस्तान में वर्ष 2021–22 में कॉटन का उत्पादन 12.63 लाख टन रहने का अनुमान है। यह उत्पादन 2020–21 में 9.80 लाख टन जबकि वर्ष 2019–20 में 13.50 लाख टन रहा। पाकिस्तान के वर्ष 2021–22 में 11.97 लाख टन कॉटन आयात करने की संभावना है, जबकि वर्ष 2020–21 में यह आयात 11. 59 लाख टन रहा। ब्राजील में वर्ष 2021–22 में 28.74 लाख टन कॉटन पैदा होने की आस है। ब्राजील में वर्ष 2020–21 में 23.56 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 30 लाख टन कॉटन पैदा हुई थी। अमरीका में वर्ष 2021–22 में 38.37 लाख टन कॉटन की उपज होने का अनुमान है जो वर्ष 2020–21 में 31.81 लाख टन एवं वर्ष 2019–20 में 43.36 लाख टन रहा।

चीन में वर्ष 2021–22 में 58.79 लाख टन कॉटन पैदा होने की संभावना है। यह पैदावार वर्ष 2020–21 में 64.23 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 59.33 लाख टन थी। टर्की में वर्ष 2021–22 में 8.27 लाख टन (वर्ष 2020–21 में 6.31 लाख टन) कॉटन पैदा होने का अनुमान है। जबकि, अन्य देशों में कॉटन का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 44.05 लाख टन (वर्ष 2020–21 में 41.50 लाख टन) रहने का अनुमान है। वर्ष 2021–22 में ब्राजील से कॉटन निर्यात 17.85 लाख टन, अमरीका से 32.11 लाख टन रहने की संभावना है।

यह निर्यात वर्ष 2020–21 में ब्राजील से 23. 98 लाख टन और अमरीका से 35.64 लाख टन रहा। चीन का कॉटन आयात आंकलन वर्ष 2021–22 के लिए 20.68 लाख टन रहने की संभावना है जो वर्ष 2020–21 के लिए 28 लाख टन और 2019–20 में 15.54 लाख टन रहा।

बांग्लादेश का आयात मार्केटिंग वर्ष 2021–22 में 18.07 लाख टन और वर्ष 2020–21 में 19.05 लाख टन और वियतनाम का आयात वर्ष 2021–22 में 16. 33 लाख टन और वर्ष 2020–21 में 15.92 लाख टन अनुमान है। पाकिस्तान वर्ष 2021–22 में 11.97 लाख टन एवं वर्ष 2020–21 में 11.59 लाख टन, इंडोनेशिया वर्ष 2021–22 में 5.44 लाख टन और वर्ष 2020–21 में 5.02 लाख टन कॉटन आयात कर सकता है। चीन का अंतिम स्टॉक वर्ष 2021–22 में 78.76 लाख टन रहने का अनुमान है। यह स्टॉक वर्ष 2020–21 में 85.46 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 80.34 लाख टन था। वर्ष 2021–22 में ब्राजील में 28. 18 लाख टन कॉटन का अंतिम स्टॉक रह सकता है। यह वर्ष 2020–21 में 24.21 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 31.36 लाख टन रहा।

अमरीका में वर्ष 2021–22 में 7.62 लाख टन कॉटन का अंतिम स्टॉक रहने का अनुमान है जबकि और वर्ष 2020–21 में 6.86 लाख टन और वर्ष 2019–20 में यह 15.79 लाख टन रहा। समूची दुनिया का फसल वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम स्टॉक 183.55 लाख टन रह सकता है जो वर्ष 2020–21 में 193.03 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 212.21 लाख टन था। दुनिया भर में वर्ष 2021–22 में 322.8 लाख हैक्टेयर में कपास की खेती होने का अनुमान है। यह खेती 2020–21 में 311.1 लाख हैक्टेयर और 2019–20 में 344.8 लाख हैक्टेयर में हुई।

भारत में कपास का बोआई अनुमान वर्ष 2021–22 के लिए 124 लाख हैक्टेयर में होने का अनुमान है। जबकि, वर्ष 2020–21 में 130 लाख हैक्टेयर में बोआई हुई। यह खेती वर्ष 2019–20 में 134 लाख हैक्टेयर थी।

जीरे की बुआई में हुई देरी से कीमतों में तेजी की उम्मीद

चालू सीजन के दौरान प्रमुख उत्पादक राज्यों में जीरे की बुआई में हुई देरी के परिणामस्वरूप अभी तक इस प्रमुख किराना जिंस की नई फसल की आवक काफी कमजोर बनी हुई है। माना जा रहा है कि जीरे की नई फसल की आवक का पर्याप्त दबाव होली के बाद ही बनेगा। इसे देखते हुए आगामी दिनों में जीरे में और तेजी आने की उम्मीद नजर आ रही है।

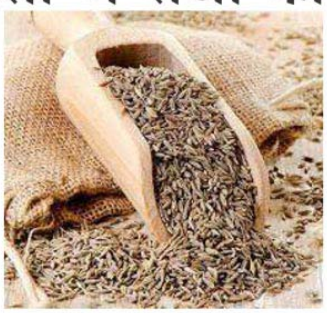

देश में गुजरात राज्य जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस राज्य में अभी तक नए जीरे की करीब एक हजार बोरियों की नाममात्र आवक ही होने की सूचनाएं आ रही हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि गुजरात में इस बार जीरे की बुआई सामान्य की अपेक्षा करीब 20–25 दिनों की देरी से आरंभ हुई थी।

पिछले सीजन के दौरान कीमत आकर्षक न मिलने के कारण किसानों की रुचि घटने से इस बार इस राज्य में जीरे की बुआई में उल्लेखनीय गिरावट आई है। गुजरात कृषि विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान सीजन की 3 जनवरी तक की अवधि में जीरे की बुआई 34.12 प्रतिशत या 1,59,100 हेक्टेयर पिछडकर केवल 3,07,100 हेक्टेयर में ही हुई है। एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि में जीरे की 4,66,200 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। जीरे की बुआई की यह गिरावट पूर्व में व्यक्त किए जा रहे अनुमानों के अनुरूप ही है। बाजारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार आमतौर पर फरवरी महीने के दूसरे पखवाड़े में बनने वाला जीरे की आवक का दबाव इस बार होली के बाद ही बनने के आसार हैं।

बहरहाल, नए जीरे की करीब एक हजार बोरियों समेत ऊंझा मंडी में इस प्रमुख किराना जिंस की कुल 8–9 हजार बोरियों की आवक होने की सूचना मिली। बहरहाल, ऊंझा में पिछले कुछ दिनों के विपरीत जीरे का उठाव भी सुधरने लगा है। दूसरी ओर, कंटेनरों का अभाव होने के कारण देश में जीरे के थोक व्यापार की सबसे बड़ी, ऊंझा, में निर्यात मांग का अभाव महसूस किया जा रहा है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि समुद्री भाड़ा भी बीते कुछ समय के दौरान बढ़ता हुआ फिलहाल करीब 5 गुणा तक ऊंचा हो गया है। भाड़े की दर आसमान पर होने के करण भी अन्य प्रमुख जिंसों के साथ–साथ जीरे की निर्यात का अभाव बना हुआ है।

आवक तुलनात्मक रूप से नीची होने और लिवाली बढ़ने से ऊंझा में जीरे की कीमत हाल ही में 100 रुपए तेज होकर फिलहाल 3775/3800 रुपए प्रति 20 किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। इससे पूर्व भी इसमें 100/150 रुपए की तेजी आई थी। भारत के अलावा विश्व में तुर्की और सीरिया को जीरे के अन्य उत्पादक देशों के रूप में जाना जाता है लेकिन अब अफगानिस्तान तथा ईरान भी चुनौती पेश करने लगे हैं। आमतौर पर तुर्की एवं सीरिया में संयुक्त रूप से करीब 35 हजार टन जीरे का उत्पादन होता है और इनकी क्वालिटी भारतीय जीरे की तुलना में हल्की होती है। आगामी दिनों में जब तक नए जीरे की आवक का पर्याप्त दबाव नहीं बनेगा, तब तक इसमें रुक–रुककर तेजी आते रहने का अनुमान है।

सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में कमी औसत भाव में बढ़ोत्तरी

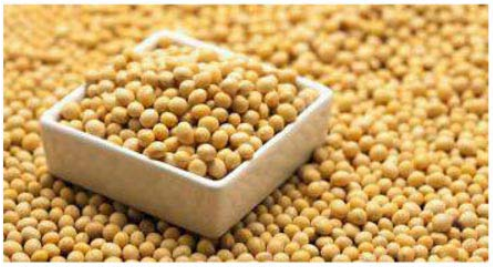

- यूएसडीए ने वर्ष 2021–22 में समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन 36.38 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है।
- अमरीकी कृषि विभाग के मुताबिक भारत में वर्ष 2021–22 में सोयाबीन का उत्पादन 119 लाख टन रहने का अनुमान जताया है।

अमरीकी कृषि विभाग ने वैश्विक तिलहन के उत्पादन में प्रतिकूल मौसम की वजह से सोयाबीन की उपज घटने का अनुमान जताया है। दक्षिण अमरीका में सूखे मौसम की वजह से यह लगातार दूसरा महीना है जब सोयाबीन के उत्पादन में कटौती आंकी गई है। हालांकि, इस कमी की भरपाई भारत में रेपसीड का उत्पादन बढ़ने से हो सकेगी। चीन एवं इजिप्त की जहां मांग कमजोर है वहीं ब्राजील, पेरुग्वे और अर्जेंटीना के निर्यात में कमी आएगी।

ब्राजील, अमरीका और अर्जेंटीना के कैरीआउट में कमी की वजह से सोयाबीन के वैश्विक अंतिम स्टॉक में कटौती की गई है। यूएसडीए ने सोयाबीन का औसत दाम वर्ष 2021–22 के लिए 40 सेंटस बढ़ाकर 13 डॉलर प्रति बुशेल किया है। यूएसडीए ने वर्ष 2021–22 में समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन 36. 38 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है, यह अनुमान पिछले महीने 37. 25 करोड़ टन था। जबकि वर्ष 2020–21 में समूची दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन अनुमान 36.62 करोड़ टन और वर्ष 2019–20 में यह 33.98 करोड़ टन था।

वर्ष 2021–22 में अमरीका में सोयाबीन उत्पादन अनुमान 12.07 करोड़ टन आंका है जो वर्ष 2020–21 में 11.47 करोड़ टन रहा। वर्ष 2019–20 में यह 9.66 करोड़ टन था। ब्राजील में वर्ष 2019–20 में सोयाबीन उत्पादन 12.85 करोड़ टन रहा जो वर्ष 2020–21 में 13.80 करोड़ टन रहा। जबकि, वर्ष 2021–22 में इसके 13.40 करोड़ टन रहने की संभावना है। अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2019–20 में 4.88 करोड़ टन रहा जिसके वर्ष 2020–21 में 4.62 करोड़ टन एवं वर्ष 2021–22 में 4.50 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

चीन में सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2021–22 में 1.64 करोड़ टन और वर्ष 2020–21 में 1.96 करोड़ टन रहने का अनुमान है। चीन में वर्ष 2019–20 में सोयाबीन का उत्पादन 1. 80 करोड़ टन रहा। वर्ष 2021–22 में चीन का सोयाबीन आयात 9.70 करोड़ टन रहने की संभावना है। यह आयात वर्ष 2020–21 में 9.97 करोड़ टन रहा। वर्ष 2021–22 में ब्राजील का सोयाबीन निर्यात वर्ष 2020–21 के 8.16 करोड़ टन की तुलना में 9.05 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया है। अमरीका का सोयाबीन निर्यात अनुमान वर्ष 2021–22 में 5.57 करोड़ टन रहने के आसार है जबकि वर्ष 2020–21 में यह 6.15 करोड़ टन रहा। अर्जेंटीना का 2021–22 में सोयाबीन निर्यात 37.50 लाख टन रहने की संभावना है।

यह वर्ष 2020–21 में 51.92 लाख टन रहा। पेरुग्वे का 2021–22 में सोयाबीन निर्यात 41.50 लाख टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2020–21 में 63.30 लाख टन रहा।

अमरीकी कृषि विभाग के मुताबिक भारत में वर्ष 2021–22 में सोयाबीन का उत्पादन 119 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। यह उत्पादन वर्ष 2020–21 में 104.50 लाख टन और वर्ष 2019–20 में 93 लाख टन रहा। भारत में वर्ष 2019–20 में 84 लाख टन सोयाबीन क्रश हुई जो वर्ष 2020–21 में 95 लाख टन पहुंच गई। जबकि, वर्ष 2021–22 में इसके 100 लाख टन रहने की संभावना है।

जीरा में मांग नहीं, उंचे भाव पर काली मिर्च

स्थानीय सियागंज किराना मंडी मे गत् हप्ते खेरची बाजार में ग्राहकी अच्छी रही थी। रात्रि में ठंड का हल्का अहसास और दिन में हल्की गर्मी होने से ग्रामीण ग्राहकी भी बढ रही बताया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, आगे नवरात्रि के बाद आगे लग्नसरा अवधि भी रहने वाली है इससे लगातार किराना वस्तुओं में ग्राहकी रहने वाली है। गत् छः महीनों में एनसीडीईएक्स वायदे बाजार में नारियल, हल्दी, जीरा और भी कई मसाला वस्तुओं पर कई बार वायदा व्यापार में उपरी भाव चलते रहे है, जिससे हाजिर व्यापार भाव भी प्रभावित होकर सर्वकालीन उपरी भाव पर सभी मसाला घटक हो गये है। सूत्रों के अनुसार, देश में पूर्व में हल्दी स्टॉक पर बेहद गलत धारणा बनाई गई है जिससे हल्दी के अपार स्टॉक के बावजूद हल्दी के भाव स्टाकिस्टो ने मुनाफे में कमी नही आने देने के कारण सटटे मे उपर ही बनाऐ रखे बताऐ गये है।

क्या देश में वाकई हल्दी का उत्पादन इतना गिर गया था?

यह स्थिति तो आकार्यजनक है जिस पर बडे कोर्पोरेट घरानो की भूमिका को शक की निगाह से तोला जा रहा है। हल्दी निजामाबाद 105 से 110 और लालगंज 133–134 पर रहती थी जिसका भाव गत् छः से आठ माह में बढते क्रम से हल्दी निजामाबाद 115 से 140 रू और लालगंज का भाव 172 से 175 रू तक हो गया है। कमजोर मांग के चलते भी हल्दी मे तेजी रही। बताया जा रहा है कि उत्पादक प्रदेश की मंडियो मे फिलहाल मांग अधिक नही होने से आवक में कमी है और उधर हल्दी मे देसावर स्टॉक तथा निर्यात कामकाज मे अधिक मांग रहने की धारणा से लंबी तेजी की धारणा भी बताई जा रही है। हांलाकि स्थानीय स्टॉकिस्ट और व्यापार जगत हल्दी का भविष्य मंदी का बताया रहा है।

जीरा का निर्यात मांग कमजोर होना बताया जा रहा है। सटोरियें वायदा मार्केट में जीरे पर भारी सटटा कर उंचा उठाने की कोशिश में लगे बताए जा रहे है। हांलाकि राजस्थान की तरफ जीरा का रकबा गत् वर्ष कमजोर था। इससे रबी के हाल ही के उत्पादन में कमी आना बताया जा रहा है। इससे कीमतो में सुधार होना बताया जा रहा है। इंदौर की थोक मंडियों में जीरा राजस्थान की तरफ का 180 से 190 रू तथा उंझा मध्यम का भाव 190 से 195 रू तक होना बताया जा रहा था।

कालीमिर्च का गत् वर्ष भी भारी उत्पादन रहा था और इस वर्ष भी कोई 50 हजार टन से अधिक की ही उम्मीद बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इतना ही उत्पादन देश में चार वर्ष पूर्व भी था, मगर अंतरराष्ट्रीय सटटबाजी और आयात– निर्यात के फेर ने इसका स्थानीय भाव 525 रू से 545 रू तक पहुंचा दिया था। छोटे व्यापारीयो के मुताबिक, शेयर मार्केट के आपरेटरो की तरह कमोडिटी के हर क्षैत्र में सिंडीकेट अधिक कार्य कर रहे है जो बाजार को अपने तरीके उठा या गिराकर मुनाफा कमा रहे है। कमोडिटी क्षैत्र में जबसे वायदा बाजार चालू हुआ है इस सटटे के बाजार ने आम उपभोक्ताओं की कमर तोड रखी है।

वायदा बाजार के प्रति सरकार का रवैया सरकार की नीति कृषको को फायदा दिलाने की है। किंतु उपभोक्ताओं के अनुसार, कृषक कितना फायदा उठा रहे है या सरकार तथा व्यापारी फायदा उठा रहे है। यह तो साफ है कि वायदा व्यापार के भारी उलट फेर में मूल–कृषक में असंतोष रहा है।

गेहूं, सरसों और चना की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान

रबी की चालू सीजन में देश में गेहूं चना और सरसों की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर हो सकती है जिससे विशेष तौर पर दलहन और तिलहन में खाद्य महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, जुलाई में शुरू हुए 2021–22 के फसल वर्ष गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.132 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 1.58 फीसदी अधिक है। सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड 1.149 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष से 12.54 फीसदी अधिक है।

इस वर्ष चना का उत्पादन 1.312 करोड़ टन के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 10.16 फीसदी अधिक है। कुल मिलाकर 31. 606 करोड़ टन (खरीफ और रबी को मिलाकर) के साथ खाद्यान्न उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर रह सकता है, जो कि पिछले वर्ष से 1.71 फीसदी अधिक है। रबी सीजन में सभी फसलों में गेहूं सरसों और चने का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी कुछ हफ्तों में इनकी पैदावार पूरी क्षमता के साथ बाजार में पहुंचना शुरू हो जाएगी।

रबी फसलों की अच्छी पैदावार से आगामी महीनों में खाद्य महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर खाद्य तेलों और दलहनों के दाम में गिरावट आ सकती है। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में सात महीनों के अंतराल के बाद देश की खुदरा महंगाई केंद्रीय बैंक की ओर से महंगाई के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा से ऊपर चली गई जबकि थोक महंगाई दर जनवरी महीने में लगातार 10वें महीने दो अंक में बनी रही। सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ समय पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर जनवरी में 6.01 फीसदी पर पहुंच गई जिसमें खाद्य, पेय, परिधान और फूटवियर का योगदान रहा। प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण सब्जियों के दाम में तेजी से इजाफा हुआ।

दिसंबर 2021 में सब्जियों के दाम में 3 फीसदी की गिरावट आई थी जो जनवरी 2022 में 5.2 फीसदी की उछाल के साथ 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, प्रमुख महंगाई दिसंबर के 5.85 फीसदी से कम होकर जनवरी में 5.82 फीसदी पर आ गई। इसमें उतार चढ़ाव वाले खाद्य और ईंधन कीमतों को शामिल नहीं किया गया है।

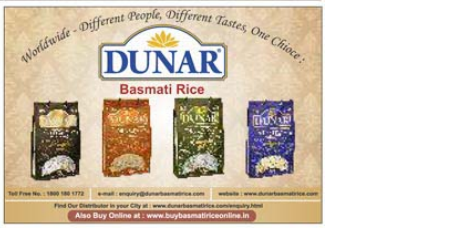

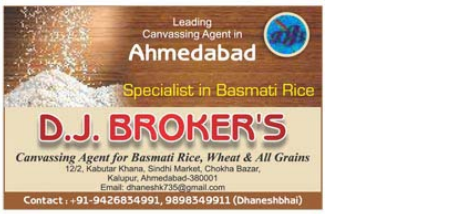

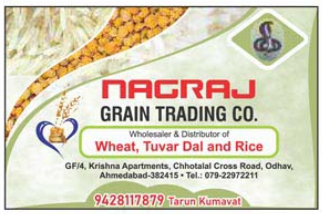

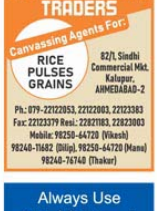

सोयामील निर्यात घटकर 1.76 लाख टन पर

सॉल्वैंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के मुताबिक, देश का सोयामील (डीओसी) निर्यात जनवरी में सालाना आधार पर 65 प्रतिशत घटकर 1.76 लाख टन रहा। मुख्य रूप से सोयाबीन और

रैपसीड मील के निर्यात में गिरावट से डीओसी की बाहर भेजी जाने वाली खेप में कमी आई है। जनवरी, 2021 में भारत का सोयामील निर्यात 5.01 लाख टन रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह अप्रैल–जनवरी के दौरान सोयामील निर्यात 35 प्रतिशत घटकर 19.43 लाख टन रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 29.69 लाख टन रहा था।

सोयामील का इस्तेमाल पॉल्ट्री और अन्य क्षेत्रों में पशुचारे के रूप में होता है। एसईए द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी में सोयाबीन एक्सट्रैक्शन का निर्यात भारी गिरावट के साथ 52,771 टन रह गया, जो एक साल पहले समान महीने में 2.83 लाख टन रहा था। इसी तरह जनवरी में रैपसीड एक्सट्रैक्शन का निर्यात घटकर 16,164 टन पर आ गया, जो एक साल पहले समान महीने में 74,240 टन था।

धान खरीद का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, 2015–16 और 2020–21 के बीच धान से लाभांवित होने वाले किसानों की संख्या खरीद में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं की खरीद से लाभांवित होने वालों में लगभग 140.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीते 6 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

अगर गेहूं की बात करें तो इसमें 140 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। ये आंकड़े वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए वादों के बाद सामने आए हैं। सीतारमण ने कहा था कि 2021–22 रबी और खरीफ मार्केटिंग सीजन में गेहूं और धान की खरीद कुल 121 मिलियन (12 करोड़ 11 लाख) टन होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 1.63 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा था कि इस खरीद के माध्यम से लगभग 2.37 ट्रिलियन रुपए का एमएसपी मूल्य सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। वित्त मंत्री के दावों के बाद ऐसी चर्चा हुई कि पिछले कुछ वर्षों में खरीद की सीमा में कटौती हुई है और साथ ही लाभांवित होने वाले किसानों की संख्या में भी कमी आई है. लेकिन भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक, 2015–16 और 2020–21 के बीच धान से लाभांवित होने वाले किसानों की संख्या खरीद में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं की खरीद से लाभांवित होने वालों में लगभग 140.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 2019–20 के रबी सीजन में लगभग 436,858 तिलहन किसानों को खरीद कार्यों से लाभ हुआ। वहीं 2020–21 के रबी सीजन में 1.1 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ। हालांकि दलहन के मामले में दो सत्रों के बीच लाभार्थियों की संख्या में मामूली गिरावट आई। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 2015–16 और 2020–21 के बीच प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, यूपी और यहां तक घ्धकि पश्चिम बंगाल में सरकारी खरीद से लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन लंबे समय से भारत का अनाज का कटोरा माने जाने वाले पंजाब में इसमें 12.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इसी तरह गेहूं के मामले में भी 2015–16 के बाद से मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में राज्य खरीद से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन पंजाब में वृद्धि केवल 5 प्रतिशत है।

खाद्य भंडारण में बढ़ोत्तरी

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से ही सबसे अधिक खरीद होती है। रबी मार्केटिंग सीजन 2019–20 के आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में उत्पादन का लगभग 73 प्रतिशत और हरियाणा में 80 प्रतिशत की खरीद हुई है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह की खरीद नीति के कारण खाद्य भंडारण बढ़ गया है और फसल विविधीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन का अनुमान

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, देश का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021–22 (जुलाई–जून) में रिकॉर्ड 11.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है। रबी की मुख्य फसल गेहूं का उत्पादन 2020–21 के फसल वर्ष में 10.95 करोड़ टन रहा था। दूसरा अग्रिम उत्पादन अनुमान जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस साल कुल खाद्यान्न उत्पादन भी रिकॉर्ड 31.60 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले फसल वर्ष में 31.07 करोड़ टन रहा था।

कृषि मंत्रालय अंतिम आंकड़ों से पहले चार बार फसल उत्पादन के अनुमान जारी करता है। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है।

वर्ष 2021–22 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों (2016–17 से 2020–21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.35 मिलियन टन अधिक है। 2021–22 के दौरान चावल का कुल उत्पादन 127.93 मिलियन टन रिकॉर्ड अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 116.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 11.49 मिलियन टन अधिक है।

हरियाणा के किसानों को 561.11 करोड़ रूपये का मुआवजा जारी

हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन–2021 के दौरान राज्य में भारी बारिश, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में किसानों को 561.11 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की शुरुआत की जा चुकी है। यह रकम 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जल्द से जल्द किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

उन्होंने उपायुक्तों को रबी–2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके। यानी इस साल भी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताकि किसानों को उनकी लागत का कुछ हिस्सा मुआवजे के रूप में मिल जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार किसान हितैषी है। किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजा पाने के लिए सालों इंतजार करते थे, अब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है।

किसान भी विश्वास करने लगे हैं कि उन्हें कम समय में मुआवजा मिलेगा। उन्होंने ने कहा कि, हमारी सरकार पिछले 7 साल से निरंतर किसानों के हितों में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

फसल बीमा योजना के अलावा किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई योजना से लेकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना तक चलाकर राज्य सरकार ने सदैव किसान भाईयों को यही संदेश दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

आर्थिक तौर पर किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।

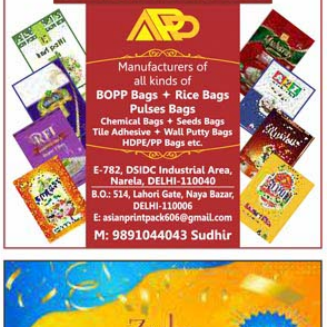

स्वामी, संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशकः टी. आर. अरोड़ा द्वारा व्यापार एक्सप्रैस के लिए 2718, गली नं. 5, बिहारी कालोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032 से प्रकाशित तथा बालाजी आफसैट उल्धनपुर 1/11884, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 से मुद्रित। संपादक-टी. आर. अरोड़ा